जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

बीकानेर

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 2200660 फैक्स : 0151-2527371 वर्षः 46 संख्याः 294 प्रभात बीकानेर, शनिवार 17 मई, 2025 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रू.

शशि थरुर भारत सरकार के संसदीय प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व करेंगे

यह प्रतिनिधि मण्डल, 22 मई को अमेरिका जायेगा, पाकिस्तान के आतंकवाद के बारे में भारत का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 मई। तिरुवन्तपुरम सांसद शशि थरुर द्वारा ऑपरेशन सिन्दूर के दौरान तथा बाद में नरेन्द्र मोदी सरकार का बचाव करने पर, जहाँ उनकी अपनी कांग्रेस पार्टी उनसे अप्रसन्न है, वहीं केन्द्र सरकार उन्हें एक महत्वपूर्ण संसदीय प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपने पर विचार कर रही है, जो अमेरिका को पाकिस्तानी आतंक के विषय में वस्तुस्थिति की जानकारी देगा, भारत सरकार ने पूरी दुनिया को पाक प्रायोजित आतंकवाद की जानकारी देने की योजना बनाई है।

शशि थरुर और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी विपक्ष के ऐसे प्रमुख नेताओं के रुपमें उभर कर आये हैं, जिन्होंने पहलगाम में हुई हत्याओं के बाद पाकिस्तान पर मोदी सरकार के हमले का जोरदार समर्थन एवं बचाव किया है। थरुर द्वारा किये जा रहे मोदी के समर्थन को कांग्रेस के आधिकारिक रुख से अलग रुप में देखा जा रहा है। यही कारण है कि कल कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि थरुर अपने निजी विचार व्यक्त कर रहे हैं, जो पार्टी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- थरुर के अलावा ए.आई.एम.आई.एम. के नेता असदुद्दीन ओवैसी विपक्ष के दूसरे नेता होंगे, जिन्हें प्रतिनिधि मण्डल में शामिल किया जायेगा।
- ओवैसी ने प्र.मंत्री मोदी की सरकार को भारी समर्थन दिया है, पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद, भारत सरकार का पाकिस्तान पर जवाबी आक्रमण को।
- हालांकि, शशि थरुर को भारत के प्रतिनिधि मण्डल का अध्यक्ष बनाना कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है, क्योंकि, थरुर विदेशी मामलात की संसदीय समिति के अध्यक्ष वैसे भी हैं।
- पर कल कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता, जयराम रमेश ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत मोदी सरकार की कार्यवाही की थरुर द्वारा तारीफ करने को उनका निजी विचार बताकर एक तरह से झिड़की दी थी, इसे देखते हुए शशि थरुर को संसदीय प्रतिनिधिमंडल का अध्यक्ष बनाना साधारण बात नहीं लग रही है।
- ओवैसी के अलावा अमेरिका जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि के अन्य सदस्य हैं, शमिक भट्टाचार्य, अनुराग ठाकुर, मनीष तिवाड़ी, प्रियंका चतुर्वेदी, संबित पात्रा, सुप्रिया सुले व डी. पुरंदेश्वरी है।

अवमानना के मामले में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक 20 को अदालत में तलब

जयपुर, 16 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट को बीस मई को अदालत में पेश होकर बताने को कहा है कि अदालती आदेश के बावजूद, याचिकाकर्ता को ब्रिज कोर्स करवाकर नियुक्ति क्यों नहीं दी गई। चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस मुकेश राजपुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश सुमन कुमारी व अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

- शिक्षा निदेशक सीताराम जाट को पेश होकर बताना है कि अदालत के आदेश की पालना क्यों नहीं हुई।

याचिका में अधिवक्ता तरुण चौधरी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2006 में भाग लिया था। याचिकाकर्ता को यह कहते हुए नियुक्ति नहीं दी गई कि वह बीएसटीसी न होकर, एनटीटी प्रशिक्षण प्राप्त है। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने 17 अप्रैल, 2008 को परिपत्र जारी कर प्रावधान किया कि एनटीटी कोर्स करने वाले छह माह का ब्रिज कोर्स कर बीएसटीसी के समान हो जाएंगे। याचिकाकर्ता को नियुक्ति नहीं देने पर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बलूच नेताओं ने हिन्दुस्तान में ''गवरमैंट इन एग्ज़ाइल'' बनाने की इजाज़त माँगी

इन बलूच नेताओं का तर्क है कि स्वतंत्र बलूचिस्तान ही एक शांत व आतंकवाद मुक्त पाकिस्तान की गारंटी है

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 मई। बलूच नेता भारत सरकार से समर्थन के साथ -साथ निर्वासित सरकार चलाने की अनुमति मांग रहे हैं।

प्रमुख बलूच नेता रज़्ज़ाक बलूच पाकिस्तान से आज़ादी की अपनी लड़ाई में भारत से समर्थन की प्रबल अपील कर रहे हैं।

अमेरिका में रह रहे रज़्ज़ाक बलूच आंदोलन के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज़ोरदार दलील पेश कर रहे हैं। डॉ. तारा चंद और कई अन्य नेताओं के साथ, वे इस आंदोलन के अग्रणी नेताओं में से एक हैं। रज़्ज़ाक बलूच का कहना है कि बलूच नेता एक स्वतंत्र देश के लिए अभियान चला रहे हैं।

बलूच नेताओं का तर्क है कि एक स्वतंत्र और संप्रभु बलूचिस्तान ही पाकिस्तान को शांति और आतंकवाद मुक्त बनाए रखने की सबसे बड़ी गारंटी है। एक स्वतंत्र बलूचिस्तान का अर्थ होगा कि पाकिस्तान अपनी विशाल सेना और सैन्य संगठनों को कायम नहीं रख सकेगा। यह पाकिस्तान को कमज़ोर करने और उसके आतंकवादी संगठनों को निष्क्रिय करने का सबसे अच्छा उपाय है।

बलूच नेता यह भी दावा कर रहे हैं कि उन्हें अपने आसपास के इलाकों में भी व्यापक जनसमर्थन प्राप्त है। वे मानते हैं कि बलूचिस्तान की आज़ादी के आंदोलन को खुलकर समर्थन देने का यह सबसे उपयुक्त समय है।

कैनडा के टैग टीवी को दिए एक इंटरव्यू में, रज़्ज़ाक बलूच ने भारत से अपील की है कि अपनी झिझक छोड़कर बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के आंदोलन का समर्थन करे। रज़्ज़ाक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- इन नेताओं के अनुसार, स्वतंत्र बलूचिस्तान बनने के बाद, पाकिस्तान एक भारी भरकम बड़ी सेना नहीं रख पायेगा। इससे पाकिस्तान के ''नाखून कट जायेंगे, यानी पाकिस्तान ''डी फैंग'' हो जायेगा तथा आतंकवादी संगठन अपने आप कमज़ोर पड़ जायेंगे।
- कैनडा के टी.वी. चैनल ''टैग टी.वी.'' को दिये गये एक इंटरव्यू में बलूच नेता रज़्ज़ाक बलूच ने भारत से अपील की कि भारत अब हिचकिचाहट छोड़े और खुलकर बलूचिस्तान के स्वतंत्रता संग्राम को समर्थन व मदद दे।
- बलूच नेताओं के अनुसार, अमेरिका, ईरान, मिडिल ईस्ट व यूरोप में बहुत संख्या में बलूच रहते हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम का पूर्ण समर्थन कर रहे हैं।
- रज़्ज़ाक बलूच के अनुसार, पश्चिमी पंजाब के पंजाबियों का कोई ''डी.एन.ए.'' कनैक्शन नहीं है, अरब देशों से या मिडिल ईस्ट के लोगों से।

'स्कूल फीस के निर्धारण के लिये अभी तक रिवीज़न कमेटी का गठन क्यों नहीं हुआ?'

राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रमुख शिक्षा सचिव से जवाब तलब किया और सोमवार को अगली सुनवाई तय की

जयपुर, 16 मई (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रमुख शिक्षा सचिव को 19 मई, यानी अगले सोमवार को शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि स्कूल फीस नियंत्रण अधिनियम, 2016 में प्रावधान होने के बावजूद, अभी तक ''फीस रिवीज़न कमेटी'' का गठन क्यों नहीं किया गया है। अदालत ने कहा कि प्रमुख शिक्षा सचिव व्यक्तिशः या वीसी के जरिए अदालत में उपस्थित होकर अपना जवाब पेश करें। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह आदेश भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता स्कूल की फीस निर्धारण को लेकर स्कूल फीस कमेटी ने निर्णय लिया था। पाठकों को बता दे कि स्कूल फीस नियंत्रण कानून के अनुसार, हर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- पाठकों को बता दें कि स्कूल फीस की दर तय करने के लिये स्कूल फीस नियंत्रण अधिनियम, 2016, के तहत तीन तरह की कमेटियों की अहम भूमिका है। पहली स्कूल फीस कमेटी, जो अध्यापकों और अभिभावकों के प्रतिनिधियों से गठित एक कमेटी होती है, जो दोनों पक्षों को सुनने के बाद आपसी समझौते से स्कूल फीस की दर तय करती है।
- दोनों पक्षों में से एक भी पक्ष अगर स्कूल फीस के निर्णय से संतुष्ट नहीं हो तो वह डिवीज़न कमेटी के समक्ष अपील दायर कर सकता है। डिवीज़न कमेटी के फैसले के विरूद्ध आखिरी अपील रिवीज़न कमेटी के समक्ष हो सकती है।

एकल पट्टा प्रकरण में अब जुलाई माह में सुनवाई

जयपुर, 16 मई। राजस्थान हाईकोर्ट में शुक्रवार को एकल पट्टा प्रकरण को लेकर सुनवाई हुई। पूर्व आईएएस जीएस संधू की ओर से मामले में अपना पक्ष रखा गया। वहीं, अदालत ने मामले में अब जुलाई माह में सुनवाई करना तय किया है। चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव की एकलपीठ ने यह आदेश पूर्व मंत्री शांति धारीवाल, जीएस संधू, निष्काम दिवाकर और ओंकार मल सैनी की ओर से दायर सात आपराधिक याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।

- पूर्व आईएएस संधू के अधिवक्ता ने बहस पूरी करने के लिये और समय मांगा

सुनवाई के दौरान, पूर्व आईएएस जीएस संधू की ओर से अधिवक्ता एसएस होरा ने तीसरे दिन भी बहस जारी रखी। इस पर अदालत ने उन्हें कहा कि वे बहस के लिए पर्याप्त समय ले चुके हैं और दूसरे वकीलों को भी बहस का मौका दिया जाए। इस पर संधू के अधिवक्ता ने कुछ समय के लिए बहस

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारत ने चिनाब पर बने सलाल व बागलिहार बाँधों से पानी को नियंत्रित किया

पाकिस्तान में हाय-तौबा मची, सिंधु नदी के सिस्टम से ही पाकिस्तान की सिंचाई की 80 प्रतिशत जरूरत पूरी होती है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 मई। भारत और पाकिस्तान के बीच एक नया और संभावित रूप से अस्थिर मोर्चा खुल रहा है जो ज़मीन को लेकर नहीं, बल्कि पानी को लेकर है। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध बिगड़ने और सीमा पर तनाव बढ़ने की वजह से भारत ने सिंधु नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करना शुरू कर दिया है, पाकिस्तान की सिंचित कृषि भूमि का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा इसी पानी पर निर्भर करता है।

भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए चिनाब नदी पर स्थित सलाल और बगलीहार बांधों से जल प्रवाह में बदलाव किया है। इस कदम से पाकिस्तान में खलबली मच गई है, और इस्लामाबाद ने तुरंत नई दिल्ली को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि पश्चिमी नदियों - सिंधु, झेलम और चिनाब के प्रवाह में किसी भी प्रकार का व्यवधान पाकिस्तान में गंभीर कृषि और आर्थिक संकट ला सकता है, जो पहले से ही जल संकट से जूझ रहा है।

यह कदम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक सख्त बयान के बाद आया है:

''आतंक और व्यापार, आतंक और बातचीत, खून और पानी एक साथ नहीं चल सकते।''

इस संदेश जिसे कई लोग बड़ा बदलाव मानते हैं, यह दर्शाता है कि अब भारत जल सहयोग को सीमा पार आतंकवाद से जोड़ रहा है, जो पहले के उस दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग है जिसमें सिंधु जल संधि को राजनीतिक तनाव से अलग रखा जाता था।

जम्मू-कश्मीर में स्थित सलाल और बगलीहार बांधों के गेट इन दिनों बंद करने से चिनाब नदी के पाकिस्तान में प्रवाह में बदलाव आया है। साथ ही, भारत ने पश्चिमी नदियों, सिंधु, झेलम और चिनाब, पर कई जलविद्युत

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- भारत के जल संसाधन मंत्रालय के विशेषज्ञों का कहना है, इंडस वॉटर ट्रिटी के प्रावधानों के तहत भारत को ''नॉन कन्ज़म्पटिव'' उद्देश्यों के भारत, इंडस वॉटर सिस्टम के पानी का उपयोग कर सकता है, जैसे हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर हाउस चलाना आदि।
- पर, पाकिस्तान के सिंचाई विभाग को कहना है, अगर सिस्टम में पानी छोड़ने की व्यवस्था व टाईम में कुछ भी परिवर्तन हुआ तो पाकिस्तान का सिंचाई का व खेती का ''चक्र'' (साइकिल) बुरी तरह प्रभावित होगा। और भारी तबाही मच जायेगी।
- पाकिस्तान की यह गुहार भारत के कानों तक पहुँची है। पर, अभी भारत किसी प्रकार ''एडजस्टमैंट'' करने के मूड में नहीं है, जब तक ''आतंकवाद'' के निर्यात की पाकिस्तान की नीति नहीं बदलती।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 22 मई को बीकानेर आएंगे

बीकानेर, 16 मई (निसं)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 22 मई को बीकानेर आएंगे। वे यहां देशनोक स्थित करणी माता मंदिर में दर्शन करेंगे। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तथा केन्द्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल बीकानेर यात्रा में मोदी के साथ होंगे। प्रधानमंत्री की बीकानेर यात्रा की सूचना के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि और एसपी कावेन्द्र सिंह सागर देशनोक में डेरा डाले हुए हैं।

- देशनोक में करणी माता मंदिर में दर्शन के साथ ही रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे।

भाजपा प्रवक्ता मनीष सोनी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देशनोक में बने आधुनिक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। देशनोक के साथ ही लालगढ़ में भी नया रेलवे स्टेशन बनकर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राजनीतिक जरूरत के कारण एन.सी.पी. के धड़े नज़दीक तो आ रहे हैं

पर, अहम् की लड़ाई व आपसी रंजिशें, विलय शायद नहीं होने देंगी

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 16 मई। महाराष्ट्र में नैशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों में प्रस्तावित विलय के सम्बंध में कई महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं, क्योंकि कई गहरे पैठे तनाव उभर आए हैं। इनमें से एक गुट के प्रमुख शरद पवार हैं तो दूसरे गुट का नेतृत्व उनके भतीजे अजीत पवार कर रहे हैं। सूत्रों ने कहा, चाचा-भतीजे के बीच पर्दे के पीछे चल रही वार्ता के बावजूद विलय प्रक्रिया सहज नहीं है ओर टकराव बढ़ाने वाली शर्तों व व्यक्तिगत शिकायकों के कारण यह प्रक्रिया पटरी से उतर सकती है।

विश्वस्त सूत्रों ने संकेत दिया कि अजीत पवार के बेहद करीबी लोगों ने विलय के लिए दो अनिवार्य शर्तें रखी हैं, सबसे पहली शर्त, शरद पवार गुट के वे नेता माफी मांगे, जिन्होंने पूर्व में अजीत पवार पर अपमानजनक और निराधार आरोप लगाए हैं। दूसरी शर्त है कि शरद पवार का गुट विलय के बाद अजीत पवार को नेता माने।

ये मांगे शरद पवार खेमे के गले नहीं उतर रही हैं। गुट के एक नेता ने इन शर्तों को नकारते हुए कहा कि ''अल्टीमेटम और दबाव की रणनीति पर आधारित विलय स्वीकार्य नहीं है। जिस तरह से अजीत पवार गुट अपनी मर्जी थोप रहा है, वह अलोकतांत्रिक है। सशर्त एकता से दूरगामी राजनैतिक सहयोग की नींव नहीं रखी जाती है।'' उक्त नेता ने अजीत गुट पर दादागिरी की राजनीति करने का आरोप लगाया।

महाराष्ट्र के राजनैतिक पर्यवेक्षक विलय की वार्ता से हैरान नहीं हैं। दोनों पक्षों के कई नेता विचारधारा परिशुद्धता से ज्यादा अपने हितों की सुरक्षा के लिए भी चिंतित है। इनमें से अधिकांश सहकारी समितियों के मुखिया हैं और उनकी अपनी चीनी मिलें, कंस्ट्रक्शन कंपनियां व कई ठेका आधारित व्यवसाय हैं। मंद होती अर्थव्यवस्था में वित्तीय चिंताओं ने उन्हें राजनैतिक तथा व्यावसायिक भविष्य सुरक्षित करने के लिए विलय पर विचार करने को मजबूर किया है।

जमीनी स्तर पर बढ़ती अनिश्चितता से पार्टी कार्यकर्ताओं की चिंता भी बढ़ गई है। शरद पवार ने खुद को सक्रिय राजनीति से दूर कर लिया है और उनके गुट के कई नेता अन्य राजनैतिक विकल्प तलाश रहे हैं, ताकि महाराष्ट्र की राजनीति में उनका अस्तित्व बना रहे।

मौजूदा राज्य सरकार स्थिर है और लगता है अपना कार्यकाल पूरा करेगी। इसे देखते हुए सत्तारूढ़ गठबंधन इन्हें आकर्षक विकल्प लग रहा है।

अटकलें हैं और कुछ राजनैतिक विश्लेषक भी यही कह रहे है कि अडानी ग्रुप के लोगों से शरद पवार की निकटता बढ़ गई है और इसी वजह से अजीत पवार के प्रति उनका रुख नरम पड़ गया है। ये घटनाक्रम हालांकि ऑफिशियल नहीं, पर इसे विश्वसनीय माना जा रहा है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- अजीत पवार ग्रुप ने कई कड़ी शर्तें भी रखी हैं: शरद पवार खेमे के सभी नेता सार्वजनिक माफी मांगें, अजीत पवार पर ''अनर्गल आरोप'' लगाने के लिए।
- दूसरी शर्त है कि विलय के बाद, शरद पवार का खेमा, विधिवत् अजीत पवार को पार्टी का नेता स्वीकार करे।
- शरद पवार खेमा इन शर्तों को अजीत पवार ग्रुप की ''दादागिरी'' मानता है तथा उनके अनुसार, सशर्त एकता, किसी सच्चे, दीर्घकालीन राजनीतिक सहयोग के रास्ते में बाधक होती है।
- पर, यह भी सच है कि एन.सी.पी. के अधिकांश नेता अपने बिज़नैस के हितों की सुरक्षा के बारे में ज्यादा चिंतित हैं, बनिस्पत कि ''सैद्धांतिक पवित्रता'' के और अब भाजपा के मु.मंत्री देवेन्द्र फडनवीस की सरकार अपना ''टर्म'' आसानी से पूरा करेगी, अतः एन.सी.पी. के नेता इस ''सत्तारूढ़ गठबंधन'' के नज़दीक रहना चाहते हैं और इसीलिए एन.सी.पी. के दोनों धड़ों के विलय की बात बार-बार उठ रही है।

प्र.मंत्री आवास पर हाईलैवल मीटिंग

नयी दिल्ली, 16 मई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार शाम अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हिस्सा लिया।

मोदी की अध्यक्षता में एक घंटे से अधिक समय तक चली बैठक में शाह के अलावा विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस बारे में आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं दी गई है, हालांकि यह माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री, विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद मौजूदा स्थिति की समीक्षा की है। इसके अलावा, आगे की रणनीति पर भी चर्चा की गई।

- मीटिंग में प्र.मंत्री मोदी के साथ गृहमंत्री शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शामिल थे।